चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री का भाषण

25 अक्तूबर, 2009

मैं थाईलैंड के प्रधान मंत्री महामहिम श्री अभीसित वैज्जजीवा को चौथे पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन करने के लिए और सर्वोत्तम व्यवस्थाएं कराने के लिए धन्यवाद देता हूं।

हम वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मंदी के समय में बैठक कर रहे हैं। जी-20 नेता तीन बार मिल चुके हैं और इस संकट का समाधान करने के लिए हमारे समायोजित प्रतिक्रिया से कुछ फर्क पड़ा है। तथापि, अभी यह कहना मुश्किल होगा कि हम इस संकट पूरी तरह उभर चुके हैं। मैं प्रधान मंत्री श्री रुड द्वारा क्षेत्र में विकास के स्रोतों का पता लगाने के लिए पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में शामिल देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के सुझाव का समर्थन करता हूं।

पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन प्रक्रिया की शुरूआत करना दूरदर्शितापूर्ण काम था। यह हमारे साझे सामर्थ्य के विश्वास का कार्य भी था। आज विश्वभर की नज़रों में एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो वैश्विक आर्थिक मंदी से उभरने में अगुवाई कर सकता है। कुछ दशकों पूर्व एशिया के बाघों ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। आज जी-20 देशों के 20 सदस्यों में से 6 सदस्य पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का हिस्सा हैं।

हमें वैश्विक आर्थिक संकट से सीख लेनी होगी। इसमें से एक यह होगी कि हमें अपनी विकास नीतियों में समन्वयन सुनिश्चित करने आवश्यकता है। दूसरी, वास्तविक अर्थ-व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ रखने जरूरत है। हम जापान के साथ इस बात पर सहमत हैं कि घरेलू आवश्यकताओं के विकास की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और तीसरा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के बहाव को खुला व्यवस्थित और आकलन करने योग्य रखने की जरूरत है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का उद्भव क्वालालामपुर में की गई हमारी प्रथम घोषणा के अनुरूप होना चाहिए जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को एक खुले समावेशी पारदर्शी और बाह्य मुखी फोरम के रूप में देखता है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है और जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। हमारे बीच आर्थिक घनिष्टता से अरबों डॉलरों का अतिरिक्त output हो सकता है।

सदस्य एशियाई देशों के बीच मुक्त व्यापार संधियों को मिलाकर एशियाई प्रादेशिक व्यापार संधि को एक रूप देना एशिया में घनिष्ठता लाकर एक समान रूप देने की परिकल्पना की ओर बड़ा कदम है। इससे व्यापक एशियाई आर्थिक समुदाय बनाने की दिशा में जाया जा सकता है।

हमें मूलभूत संरचना में निवेश, सृजन और सामाजिक कल्याण व्यवस्था, हमारे कामगारों के कौशल विकास और पर्यावरण अनुकूल तथा समावेशी विकास के माध्यम से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अधिक मज़बूत घरेलू मांग का सृजन करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

भारत पूर्वी एशिया में आर्थिक सहयोग, व्यवस्था और उदारीकरण के तीन स्तंभों के संबंध में व्यापक आर्थिक भागीदारी पर चरण - II की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का स्वागत करता है। हमारा मानना है कि

आर्थिक और वित्तीय घनिष्ठता के रोडमैप पर जल्दी अमल करना हमारे बीच सहयोग की दिशा में सही कदम होगा।

भारत इस प्रक्रिया में अपना भाग अदा कर रहा है। हमने सिंगापुर और कोरियाई गणराज्य के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी संधि और हाल ही में आसियान के साथ ट्रेड इन गुड्स संधि की है। हम जापान, चीन, थाईलैंड, और मलेशिया तथा अन्य देशों के साथ इसी प्रकार की संधियां करने के लिए वार्ताएं कर रहें हैं।

पूर्वी एशियाई शिखर क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक घनिष्ठीकरण, खास कर मूलभूत संरचना विकास और कनेक्टिविटी के क्षेत्र की ब्लूप्रिंट विकसित करने के लिए आसियान के आर्थिक अनुसंधान संस्थान और पूर्वी एशिया (ईआरएआई) के प्रस्ताव अच्छे हैं और इन्हें हमारे प्रोत्साहन की जरूरत है। भारत 10 वर्षों के समय के दौरान ईआरएआई की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दस लाख अमरीकी डालर का सहयोग खुशी से देगा।

हमें इस बात से काफी प्रोत्साहन मिला है कि सम्मेलन में भारत के बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर एक वक्तव्य को स्वीकर किया जाएगा। यह नालंदा Mentor समूह द्वारा कई महीनों के अथाह परिश्रम का नतीजा है और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोगात्मक कार्रवाई का एक जीवन्त उदाहरण होगा। मैं अपने सिंगापुर के साथी द्वारा इस विचार के लिए दी गई सम्बद्धता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

विश्व के सम्मुख जलवायु परिवर्तन का मुद्दा एक बड़ी चुनौती है परंतु यह ख़ासकर एशिया में विकासशील और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रहा है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन प्रक्रिया को सतत विकास के एक कारगर मॉडल को अपनाना होगा। वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण इसके मुख्य हिस्से हैं। हमारे सामने एक ऐसी वैश्विक प्रणाली की खोज करने की चुनौती है जो निजी क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के विकास और नई खोजों के लिए प्रोत्साहनों का रक्षण करते हुए साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करे कि ऐसी तकनीकें प्राप्य रहें ताकि विकासशील देशों के लिए एक वहनीय खर्च पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

हममें से कई देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। समुद्री लूट, अंतर्राष्ट्रीय गुटों और अतिवादी विचारधाराओं जैसे गैर-पारम्परिक स्रोतों के बढ़ते खतरे हैं। मैं इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति से सहमत हूं। इसमें आने वाले समय में बढ़ते और सहयोगात्मक रवैये की जरूरत है। हमें सामाजिक बहिष्कार, और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना होगा। महामारियों के खिलाफ लड़ाई और आपदा प्रबंधन में सहयोग ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में काफी सामर्थ्य है। अगर हम अपने सामूहिक ज्ञान और संसाधनों को एकजुट करें तो इसमें कोई शक नहीं कि तेजी से बदलती दुनिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शांति, स्थिरता और समृद्धि की ओर एक आशा की किरण बनेगा।

धन्यवाद।

***